facilities of Speed Post are available at present; and

(b) what are the details of plans for 1991-95 for extending such facility to remaining cities in the above States particularly during 1991-92?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The speed post facilities are available in the following cities/towns in Rajasthan and Orissa:

RAJASTHAN

(i) *Under National Network as well as point to point speed post service*

JAIPUR

(ii) *Under point to point speedpost service.*

1. Ajmer
2. Jodhpur
3. Pali
4. Bikaner
5. Kota
6. Udaipur

ORISSA

(i) *Under National Network as well as point to point Speed post service*

1. Bhubaneshwar
2. Cuttuck

(ii) *Under point to point Speed post Service*

1. Rourkela
2. Baripada
3. Balasore
4. Puri
5. Sambalpur
6. Paradeep (Port)
7. Berhampur
8. Balangir

(b) There is no plan at preesnt for 1991-95 and particularly during 1991-92 for extending speed post facilifty to remaining cities of Rajasthan and Orissa.

Improvement in Telecom Services in the country

2325. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is af act that at his Press-Conference at Chandigarh on 30th November, 1991, he had announced a provision of Rs. 40,000/- crores for the Telecommunication Department during the Eighth Plan for improving telecom services in the country;

(b) if so, what are the details of the funds proposed to be provided by borrowings, internal generation and other sources;

(c) whether Rajasthan's demand for providing each Panchayat with STD facility by the years 1992-95 is likely to bet met; and

(d) the allocation made during the current financial year as well as during the Eighth Plan period for expansion of telecommunications network in the State particularly in the rural areas?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) The draft 8th Plan proposals of the Department of Telecommunications envisage an outlay of Rs. 40,555 crores for the expansion and improvement of the telecommunications services. The proposal envisages internal resources to the extent of nearly 75 per cent and the remainder nearly 25 per cent to be borrowed from the market.

(c) Yes, Sir, by March, 1995.

(d) The Budgetary estimate for 1991-92 provides for an outlay of Rs. 34.14 crores for Rajasthan Telecom Circle for development of the telecommunications services including the Rural Areas. Depending upon the approved plan outlay allocation is made to the respective units on year to year basis.

देश में संचार प्रणाली का विस्तार

2326. श्री रजनी रंजन साहू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इक्कीसवीं सदी में संचार प्रणाली के महत्व को मद्दे नजर रखते

हुए तथा विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के विचार से सरकार संचार प्रणाली के विस्तार के लिए निकट भविष्य में कोई श्वेत पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लेने का विचार रखती है;

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में उपलब्ध टेलीफोन सुविधाओं का प्रति व्यक्ति अनुपात क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों के कौन-कौन से ब्लाक पहले ही एस०टी०डी० सेवा से जुड़े हैं और हर घर में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में 31 मार्च,1991 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में टेलीफोनों का अनुपात प्रति 100 व्यक्ति के लिए 0.6 है जबकि अन्य विकासशील देशों जैसे ब्राजील और मलेशिया में 1 जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार यह अनुपात प्रति 100 व्यक्ति क्रमशः 6.01 और 8.02 है।

(ग) सभी राज्यों की राजधानियों और 427 जिला मुख्यालयों (कुल 479 में से) में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 8वीं योजना के मसौदा प्रस्तावों में टेलीफोन नेटवर्क को और अधिक सुगम बनाने पर अधिक जोर दिया गया है। प्रस्तावित उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

—सभी ग्राम पंचायतों में 1.4.95 तक फोन सुविधा प्रदान करना।

—1.4.1997 तक 1.5 लाख अतिरिक्त ग्रामों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।

—शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 घरों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।

दिल्ली और मुम्बई में सड़कों के किनारे टेलीफोन बूथ

2327. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुम्बई और दिल्ली, सड़कों के किनारे टेलीफोन बूथ बनाने का विचार रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) जी हां, महानगर टेलीफोन निगम लि० पहले से ही इस प्रकार के बूथ सड़कों के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदान करता रहा है बशर्ते कि सड़कों के किनारे इस प्रकार के बूथों के लिए स्थान उपलब्ध हो तथा इस प्रकार के बूथों पर जहां आदमी नहीं लगाए जाते, ऐसी स्थिति में उपकरणों की चोरी तथा क्षति पहुंचाने जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

2328. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान गुजरात में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया;

(ग) 1991-92 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू किया जाना